जन संचार एवं मीडिया प्रकोष्ठ
उ0प्र0 वॉटर सैक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना, पैक्ट
वाल्मी भवन, सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

श्री शिवपाल सिंह यादव ने केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री अरूण जेटली से भेंट कर प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही सिंचाई योजनाओं की दी जानकारी

बाढ़–सूखा की समस्या से जूझते हुए उ0प्र0 ने द्वितीय हरित क्रान्ति की लम्बित योजनाओं को किया पूरा

30 साल की लम्बित परियोजनाओं को सरकार ने तीन साल में किया पूरा, जिसकी की गई विश्व बैंक द्वारा सराहना

लम्बित अधूरी परियोजनाओं के लिए की आवश्यक धनराशि की मांग

–शिवपाल सिंह यादव

लखनऊ–16 अक्टूबर, 2015

उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं राजस्व मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने आज केंद्रीय वित्तमंत्री श्री अरूण जेटली से नई दिल्ली स्थिति उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात कर प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए लम्बित योजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि की मांग की। उन्होंने बताया कि द्वितीय हरित क्रान्ति लाने के लिए वर्षों से लम्बित अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का संकल्प प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है तथा बाढ़ की समस्या से बचने के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की गयी हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 09 जिलों में निर्माणाधीन सरयू राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में एम0ओ0यू के बावजूद रू0 2051 (रूपये दोहजार इक्यावन) करोड़ केन्द्रांश का बकाया है। राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट में कार्य चालू रखने के लिए रु. 541 (रुपये पांचसौ इकतालीस) करोड़ केन्द्रांश की प्रत्याशा में अवमुक्त किये गये हैं। उन्होंने कहा कि यह जानकार आश्चर्य होगा कि ये परियोजना 30 वर्षों से चल रही है और इसकी लागत रु. 300 (रुपये तीन सौ) करोड़ से बढ़कर रु. 12000 (रुपये बारहहजार) करोड़ रुपये हो गयी है।

श्री यादव ने बताया कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ए.आई.बी.पी. (AIBP) के अन्तर्गत अर्जुन सहायक परियोजना रु. 114 (रुपये एक सौ चौदह) करोड़ केन्द्रांश बकाया है और अब पुनिरीक्षत लागत के अनुसार रु. 656 (रुपये छह सौ छप्पन) करोड़ अतिरिक्त धनराशि की

आवश्यकता होगी। सोनभद्र में बाण सागर परियोजना, बिजनौर में मध्य गंगा परियोजना तथा बाढ़ की विभिन्न परियोजनाओं के केन्द्रांश अनुमानित रु. 450 करोड़ लम्बित है। **कुल केन्द्रांश बकाया रु. 2656 (रुपये दोहजार छह सौ छप्पन) करोड़ तथा केन्द्र की प्रत्याशा में राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त रु. 860 (रुपये आठसौ साठ) करोड़ है।**

सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि गत 10 से 30 वर्षों से लम्बित, आधुनिक टैक्नोलॉजी, टर्न की कार्य–प्रणाली के कारण पिछले तीन वर्ष में जो कार्य हुए उसकी प्रशंसा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय फोरम्स द्वारा की गयी है। उन्होंने कहा केन्द्रांश अवमुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को तथा सिंचाई मंत्री द्वारा, जल संसाधन मंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग तथा वित्तमंत्री जी को पत्र लिखकर ध्यान आकर्षित किया गया। यदि वित्तीय पोषण की गम्भीर समस्या का ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो इन सभी अधूरी परियोजनाओं (जिन पर लगभग 65 प्रतिशत कार्य हो चुका है) की लागत हजारो–करोड़ रुपये बढ़ जायेगी।

श्री यादव जी ने अनुरोध किया कि वित्त सचिव, भारत सरकार के स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक कर के समयबद्ध रूप से समस्या का हल निकालने के लिए रोडमैप तय हो जाये जिससे कि 15 दिन बाद सुविधानुसार वित्तमंत्री जी के स्तर पर अन्तिम निर्णय लिया जा सके। इन सभी परियोजनाओं की अत्यविधिक लागत आंकते हुए तथा प्रदेश में अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे कि कनहर, ऐरच, बबीना, बदायूँ सिंचाई परियोजना आदि के वित्तीय पोषण के लिए लगभग रु. 15000 (रुपये पन्द्रह हजार) करोड़ की आवश्यकता होगी। दीर्घ कालीन किश्तों पर एवं कम ब्याज पर केन्द्र सरकार के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे कि एशियन डवलपमेन्ट बैंक, ब्रिक्स तथा भारतीय बैंक जैसे कि नाबार्ड से वार्ता करके पैकेज बनाया जाना शीघ्र आवश्यक होगा।

सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि गंगा–जमुना का पुनर्जीवन माननीय प्रधानमंत्री जी की उच्च प्राथमिकता है। इसके क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश सिंचाई के प्रमुख सचिव एवं अभियन्ताओं द्वारा एक अभिनव कार्य योजना बनायी गयी है, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष केन्द्र सरकार के सम्बन्धित वरिष्ठ मंत्रीगणों की उपस्थिति में चर्चा की जा सकती है, ताकि नई सोच से गंगा–जमुना का पुनर्जीवन हो सके। इस अवसर पर प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन श्री दीपक सिंघल भी मौजूद रहे।

सम्पर्कसूत्रः अशोककुमार, सूचनाअधिकारी, मो0–8738944701
email-kashoksuchana007@gmail.comफैक्स 0522–223766